



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण 1938 (श10)

(सं0 पटना 1183) पटना, बुधवार, 13 दिसम्बर 2017

सं0 ए/विविध(53)-18/2012-10228

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

संकल्प

28 नवम्बर 2017

**विषय:-** वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण सह-पुनर्वासन (Surrender-cum-Rehabilitation) योजना (संकल्प ज्ञापांक 11144 दिनांक 12.12.2013 द्वारा प्रवृत्त) को राज्य सरकार के अपने संसाधन से दिनांक 31.03.2016 के पश्चात् प्रभावी बनाए रखने के संबंध में।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक 18015/21/2012-NM-III दिनांक 04.04.2013 में निहित दिशा-निर्देश के आलोक में राज्य में संकल्प ज्ञापांक 11144 दिनांक 12.12.2013 द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण सह-पुनर्वासन (Surrender-cum-Rehabilitation) हेतु नीति का निर्धारण किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उन वामपंथी उग्रवादियों की सहायता करना था, जो हिंसा का त्याग कर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते थे। यह योजना एक बहुउद्देश्यीय रणनीति का अंग था, जिसका कार्यान्वयन हिंसा करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के समानान्तर किया गया। यह योजना वामपंथी उग्रवाद से विमुख लोगों को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने से संबंधित थी, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें एवं पुनः वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों में शामिल न हों।

2. संकल्प ज्ञापांक 11144 दिनांक 12.12.2013 द्वारा प्रवृत्त वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण सह-पुनर्वासन योजना राज्य में दिनांक 01.4.2013 से 31.03.2016 तक प्रभावी थी। योजना के बेहतर परिणाम को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधन से इसे दिनांक 31.03.2016 के पश्चात् भी जारी रखने का निर्णय लिया है, ताकि वामपंथी उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सफलता प्राप्त हो सके।

3. वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वासन योजना हेतु निम्नांकित नीति निर्धारित की जाती है :

**उद्देश्य :-**

- वामपंथी उग्रवाद में फँसा महसूस कर रहे उग्रवादियों को वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों से अलग करना।
- इसे सुनिश्चित करना कि आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी पुनः वामपंथी उग्रवादी आन्दोलन की ओर आकृष्ट न हों।

**नोट :-** सुनियोजित रणनीति के तहत आत्मसमर्पण कर इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक उग्रवादियों को आत्मसमर्पण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 4. पात्रता:-

- (i) उक्त नीति के तहत यह योजना उन वामपंथी उग्रवादियों पर प्रभावी होगी, जो शस्त्र सहित/रहित समर्पण करते हैं।
- (ii) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित समर्पण-पुनर्वासन समिति यथोचित जाँच कर पात्रता निर्धारित करेगी।
- (iii) यह योजना लागू होने के पूर्व समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों पर प्रभावी नहीं होगी।

## 5. योजनान्तर्गत लाभ :-

- (i) उच्च स्तरीय वामपंथी उग्रवादियों जैसे- (क) राज्य समिति के सदस्य, (ख) क्षेत्रीय समिति के सदस्य, (ग) केन्द्रीय समिति के सदस्य, (घ) पोलित ब्यूरो के सदस्य के समर्पण करने पर तात्कालिक सहायता के रूप में ₹ 2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) एवं मध्यम/निम्नस्तरीय वामपंथी उग्रवादियों जैसे- (क) एरिया कमान्डर, (ख) उपक्षेत्रीय कमान्डर, (ग) क्षेत्रीय कमान्डर, (घ) जाँच-सह-पुनर्वासन समिति द्वारा इंगित अन्य हार्डकोर वामपंथी उग्रवादी को ₹ 1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार) देय होगी। इस राशि को आत्मसमर्पित व्यक्ति के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक में रखा जायेगा जो आत्मसमर्पण करने की तिथि से 3 (तीन) साल पूरा करने पर उन्हें भुगतये होगा, बशर्ते उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुशंसा की गयी हो।
- (ii) उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पित हथियारों, विस्फोटकों के लिए उन्हें निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि देय होगी :-

क्र०	हथियार	प्रोत्साहन राशि
1	एल0एम0जी0 / जी0पी0एम0जी0 / पीका / आर0पी0जी0 / स्नाइपर रायफल / रॉकेट प्रक्षेपक / समानांतर हथियार	₹35,000 प्रत्येक हथियार
2	ए0के0 47 / 56 / 74 रायफल	₹25,000 प्रत्येक हथियार
3	पिस्टल / रिवाल्वर / एस0एल0आर0 / कार्बाइन / स्टेनगन / 303	₹10,000 प्रत्येक हथियार
4	रॉकेट	₹1,000 प्रत्येक हथियार
5	ग्रेनेड / हैंड ग्रेनेड / स्टिक ग्रेनेड	₹500 प्रत्येक हथियार
6	रिमोट कंट्रोल उपकरण	₹3,000 प्रत्येक उपकरण
7	एम्पूनिशन सभी प्रकार के	₹3 प्रत्येक
8	आई0ई0डी0 (Improvised Explosive Device)	₹1,000 प्रत्येक
9	माइन्स	₹3,000 प्रत्येक
10	विस्फोटक सामग्री	₹1,000 प्रति किलोग्राम
11	वायरलेस सेट (अ) कम रेंज (ब) ज्यादा रेंज	₹1,000 प्रति सेट ₹5,000 प्रति सेट
12	सेटेलार्ड फोन	₹10,000 प्रति सेट
13	वी0एच0एफ0 / एच0एफ0 कम्यूनिकेशन सेट	₹5,000 प्रति सेट
14	इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स अन्य डेटोनेटर्स	₹50 प्रत्येक ₹10 प्रत्येक

## नोट:-

- (क) दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि आत्मसमर्पण करने वाले के नाम से बैंक में सावधि जमा करायी जायेगी जो उसे आत्मसमर्पण के तीन साल बाद भुगतये होगी, बशर्ते उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदन किया गया हो।

- (iii) इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखनेवाले को उसकी रुचि के अनुसार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्हें अधिकतम 36 माह तक ₹4,000 प्रति माह भत्ता देय होगा। यदि आत्मसमर्पित को कोई सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है तो उसका प्रतिमाह देय भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

6. **हथियारों की देख-रेख**—वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पित हथियारों एवं गोला बारूद को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पुलिस महानिदेशक द्वारा की जाएगी।

7. **पुनर्वासन हेतु उग्रवादियों के पहचान का तरीका :-**

(क) वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण एवं पुनर्वासन की पात्रता राज्य स्तरीय समर्पण-सह-पुनर्वासन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी :-

(i) इस योजना के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक (विशेष शाखा) "समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी (एस0एण्ड0आर0 पदाधिकारी)" के रूप में कार्य करेंगे और वे समिति के अध्यक्ष भी होंगे;

(ii) विशेष सचिव गृह विभाग (विशेष शाखा), जो भारतीय पुलिस सेवा के हों - सदस्य ;

(iii) पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) - सदस्य ;

(iv) निदेशक (नियोजन एवं प्रशिक्षण), श्रम संसाधन विभाग - सदस्य ;

(v) पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) - सदस्य ; एवं

(vi) पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक (सशस्त्र सीमा बल) - सदस्य ;

(ख) वामपंथी उग्रवादी सी0ए0पी0एफ0 के किसी यूनिट, जिला दण्डाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) या राज्य सरकार द्वारा अन्य नामित पदाधिकारी के साथ-साथ सेना के किसी यूनिट अथवा राज्य के बाहर सी0ए0पी0एफ0 के किसी यूनिट के समक्ष समर्पण कर सकता है।

(ग) वामपंथी उग्रवादी ने जिस पदाधिकारी के समक्ष समर्पण किया है, उसे समर्पित उग्रवादी को सुरक्षा प्रदान करना होगा तथा उसकी सभी आवश्यक जानकारी विहित प्रपत्र में भरने के पश्चात उसे समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी शिविर में भेज देना होगा। समर्पित उग्रवादी के संबंध में 15 दिनों के भीतर उसके समर्पण के संबंध में निर्णय लेने की अनिवार्यता होगी।

(घ) वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वासन के लिए राज्य स्तरीय समर्पण-सह-पुनर्वासन समिति के सहयोग हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्त्रीनिंग समिति होगी, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक एवं विशेष शाखा के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

(ङ) **जॉच प्रक्रिया हेतु मानक :-**

(i) वैसे वामपंथी उग्रवादी, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें कंडिका-5 (i) में परिभाषित वामपंथी उग्रवादी कैडर का होना चाहिए तथा उसका समर्पण राज्य सरकार द्वारा संचालित व्यापक समर्पण-सह-पुनर्वास योजना के अनुरूप होना चाहिए।

(ii) राज्य सरकार द्वारा इस आशय के लिए निर्दिष्ट समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी को पूर्ण समाधान होना चाहिए कि समर्पित उग्रवादी सही मायने में वामपंथी उग्रवादी कैडर का है। समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर द्वारा आत्मस्वीकृति (confession) किया जाना चाहिए, जिसमें उसके द्वारा किए गए सभी आपराधिक कृत्यों के साथ-साथ षडयंत्र का नाम, अन्य भागीदार, वित्तपोषकों का नाम, शरणदाताओं, संदेशवाहकों, वामपंथी उग्रवादी संगठन से संबंधित विस्तृत ब्योरा हथियार/ गोला-बारूद एवं वामपंथी उग्रवादी कैडर द्वारा लूटी गई/ बाँटी गई/ व्ययनित सम्पत्ति के साथ-साथ जिस वामपंथी उग्रवादी कैडर से वह संबंधित है, उसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी।

(च) समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर से संबंधित सदस्यों की गतिविधि की जानकारी संबंधित प्राधिकार/संगठन से प्राप्त होते ही समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति समर्पण के संबंध में निर्णय लेगी तथा स्वीकार योग्य होने पर उसे पुनर्वास हेतु चयनित कर लेगी।

(छ) पुनर्वास हेतु चयनित वामपंथी उग्रवादियों को उनकी इच्छा/अभिरुचि के अनुरूप व्यवसाय/वोकेशनल प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे प्रशिक्षणों की व्यवस्था/संचालन करेगी तथा इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी को सूचना देगी। साथ ही राज्य सरकार समर्पण-सह-पुनर्वासन पदाधिकारी को मासिक भत्ता प्रदान करने हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराएगी, ताकि प्रत्येक महीने भुगतान किया जा सके। भत्ते की दर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ निर्गत अधिसूचना के आधार पर होगी।

8. **न्यायालय संबंधी मामले**—समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर के सदस्यों द्वारा किये गए गंभीर आपराधिक कृत्यों का विचारण सक्षम न्यायालय में जारी रहेगा। राज्य सरकार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर के सदस्यों के पूर्व आपराधिक इतिहास/व्यक्तिगत आपराधिक कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न मामलों में अभियोजन वापसी के संबंध में भी आवश्यक विचार करेगी। लघु अपराधों में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वविवेक से plea bargaining की अनुमति दी जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा

निर्धारित माप दण्डों के आधार पर समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर के सदस्यों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर के सदस्यों के मामले में त्वरित विचारण हेतु त्वरित न्यायालयों का गठन आवश्यकतानुसार कर सकेगी।

**9. पुनर्वासन प्रक्रिया ।**—समर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव/सचिव पुनर्वास पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किये जाते हैं। पुनर्वास पदाधिकारी समर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वासन से संबंधित रोजगार/स्वरोजगार हेतु तथा आवश्यकता पड़ने पर इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुदान की राशि (दो लाख पचास हजार रुपये/एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु राज्य के सभी विभागों के बीच समन्वय का काम करेंगे।

**10. योजना के प्रभावी होने की तिथि :-**

- (क) यह योजना दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से लागू होगी।
- (ख) इस योजना के अन्तर्गत राशि का आवंटन एवं व्यय पूर्व निर्धारित मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष-2055, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-जिला पुलिस उप शीर्ष-0003-वामपंथी उग्रवादियों का प्रत्यर्पण, विपत्र कोड-22-2055001090003 विषय शीर्ष-0003.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन से किया जाएगा।
- (ग) वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वासन हेतु भारत सरकार द्वारा यदि कोई नई नीति विहित की जाती है अथवा पूर्व में प्रवृत्त योजना की अंतिम निर्धारित तिथि (दिनांक 31.03.2016) के पश्चात विस्तारित किया जाता है तो इसके प्रभावी/विस्तारित होने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा लागू इस नीति में व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से करायी जा सकेगी एवं आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत लाभ देय होगा एवं पुनर्वासन की मदवार दर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि अथवा कंडिका-5 में निर्धारित दर, दोनों में जो अधिक हो, होगी।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक(रिल सहित)/सभी समादेष्टा, सैन्य पुलिस बल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जितेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1183-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>